शनिवार, 1 अगस्त, 2020

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

जसप्रीत बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

29 साल बाद संतोषी के साथ सनी

Page-05

प्लेबैक गायिका जमुना रानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन

बॉलीवुड-दक्षिण भारतीय संगीत उद्योग को अपनी अनूठी और सुरीली आवाज से दशकों तक समृद्ध करने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका जमुना रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। उन्होंने गुरुवार शाम बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत और उनके लाखों फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार कल्लाहल्ली में संपन्न होगा। साल 1938 में आंध्र प्रदेश में जन्मीं जमुना रानी ने महज सात साल की नन्हीं उम्र में ही फिल्म उद्योग में कदम रख दिया था और अपनी प्रतिभा के बल पर संगीत इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। जमुना रानी ने अपने गायन करियर की शुरुआत फिल्म 'त्यागय्या' से एक प्लेबैक सिंगर के रूप में की थी। अपने लंबे और सफल करियर के दौरान उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 6000 से भी अधिक गीतों को अपनी आवाज दी। उनकी विशिष्ट और अलग आवाज उन्हें अपने दौर के अन्य गायकों से अलग बनाती थी। उनकी आवाज विशेष रूप से क्लब डांस नंबर, जिप्सी सॉन्ग्स और लोकगीतों के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती थी। साल 1952 में रिलीज़ हुई फिल्म 'कल्याणी' के जरिए उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। तेलुगु सिनेमा में जमुना रानी ने कई सदाबहार गीतों के जरिए अपार लोकप्रियता हासिल की।

किसानों से ऊर्जा सुरक्षा तक मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

₹4.41 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और हरित विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 4 लाख 41 हजार 209 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य एक ओर किसानों की आय को स्थिर आधार देना है, वहीं दूसरी ओर देश को ऊर्जा, खेल और हरित विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निवेश बढ़ाने पर है।कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का रहा। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना के संचालन के लिए 3 लाख 15 हजार 614 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को बुआई और खेती के अन्य कार्यों के दौरान समय पर नकदी उपलब्ध होगी, साहूकारों से महंगा कर्ज लेने की जरूरत कम होगी और बीज, उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीदने में आसानी होगी। सरकार के अनुसार अब तक इस योजना के जरिए 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है।स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले पांच वर्षों में जलाशयों, नहरों और औद्योगिक जलाशयों पर 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी और बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। परियोजना में ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी शामिल होगी, जिससे बिजली की अधिक मांग के समय राज्यों को बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अनुमान है कि इससे हर साल लगभग एक करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा और 16 से 17 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।खेल क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना के लिए कुल 36 हजार 441 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें 29 हजार 54 करोड़ रुपये खेलो इंडिया के लिए और 7 हजार 387 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस निवेश से खेल अवसंरचना मजबूत होगी, खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा और भारत के ओलंपिक तथा पैरालंपिक प्रदर्शन को नई गति मिलेगी। साथ ही महिला खिलाड़ियों, पैरा एथलीटों और पारंपरिक भारतीय खेलों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

PoJK से रूस तक विदेश मंत्रालय का सख्त संदेश पाकिस्तान पर तीखा हमला

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर बल प्रयोग बेहद चिंताजनक है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। भारत ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के प्रति पाकिस्तान का रवैया पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है।रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारियों को "दुश्मन" बताए जाने वाला बयान वहां की सत्ता के रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि PoJK के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कथित गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है और भारत भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की आतंकवाद संबंधी नीति पर भी निशाना साधा। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि जिन आतंकियों को वर्षों तक प्रशिक्षण, हथियार और आर्थिक सहायता देकर तैयार किया गया था, वही अब पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। भारत ने इसे पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीति की बड़ी स्वीकारोक्ति बताते हुए कहा कि जिस आतंकवादी ढांचे को पाकिस्तान ने खड़ा किया, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है।

दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने चली रणनीतिक चाल

बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार ने मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंत्री पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने पूछा था कि जब दीपक प्रकाश न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वे संविधान में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बने रह सकते हैं। इसी बीच खबर है कि भाजपा के विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे दीपक प्रकाश के लिए परिषद का रास्ता साफ हो सकता है।सूत्रों के अनुसार, भाजपा और एनडीए सरकार ने यह कदम संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और दीपक प्रकाश का मंत्री पद बरकरार रखने की रणनीति के तहत उठाया है। माना जा रहा है कि खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा, जिससे वे विधायिका के सदस्य बन जाएंगे और उनके मंत्री पद पर बना रहने का संवैधानिक आधार मजबूत हो जाएगा।यह मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद चर्चा में आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार से पूछा कि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने संविधान में तय समय-सीमा से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। कोर्ट ने इसे संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है।दरअसल, हाल ही में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला था। ऐसे में उनके सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि किसी भी मंत्री को निर्धारित अवधि के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इसी स्थिति से निकलने के लिए भाजपा ने अपने कोटे की एक सीट खाली करने का फैसला किया। इसी क्रम में भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। देवेश कुमार राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों में शामिल थे और उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल कोटे से दीपक प्रकाश को मनोनीत किया जा सकता है।

शनिवार का दिन E20 पेट्रोल के विरोध के लिए अहम

शनिवार का दिन E20 पेट्रोल के विरोध के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि AAP के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपना राष्ट्रीय अभियान शुरू करेंगे और एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला साइलेंट मार्च और भूख हड़ताल के ज़रिए अपना आंदोलन तेज़ करेंगे। केंद्र सरकार के E20 (20% इथेनॉल-मिला पेट्रोल) प्रोग्राम के ख़िलाफ़ अपने राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत से ठीक पहले, केजरीवाल ने शुक्रवार को लोगों को संकेत दिया कि एक जाने-माने व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होंगे। यह तब हुआ जब पूनावाला, जिन्होंने 5 जुलाई को इथेनॉल-ब्लेंडिंग के मुद्दे पर पहला ज़मीनी विरोध प्रदर्शन किया था, ने घोषणा की कि वे गांधी स्मृति तक मार्च करेंगे और भूख हड़ताल शुरू करेंगे। केजरीवाल ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया कल (1 अगस्त) 'E20 के ख़िलाफ़ नेशनल टाउन हॉल' में देश की एक जानी-मानी हस्ती मेरे साथ होंगी जो लोगों की समस्याएं सुनेंगी और E20 पर कोई 'फ़ैसला' लेंगी। आप भी अपने विचार साझा करने ज़रूर आएं। 27 जुलाई को AAP हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कैंपेन की घोषणा करते हुए, केजरीवाल ने E20 पॉलिसी के खिलाफ अपने कैंपेन को हाल ही में हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के आंदोलन से जोड़ा, जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड:

ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को ताहिर हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगों से जुड़े अन्य गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने सभी पांच आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा बनने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने जैसे आरोप शामिल थे। सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

पुलिस का तर्क था कि यह मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" श्रेणी में आता है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने का फैसला किया।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ताहिर हुसैन दंगे के दौरान हिंसा भड़काने, दुश्मनी फैलाने, आपराधिक बल का इस्तेमाल करने, आपराधिक साजिश रचने और अंकित शर्मा की हत्या में शामिल पाए गए। ताहिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। फैसले के बाद पार्टी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि निलंबन के बाद उसका ताहिर हुसैन से कोई संबंध नहीं रहा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन और अन्य दोषी एक हिंसक भीड़ का हिस्सा थे।

PoJK में मानवाधिकार संकट का दावा

UKPNP ने संयुक्त राष्ट्र से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) ने गंभीर चिंता जताई है।पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र जांच, नागरिकों की सुरक्षा और कथित दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है।

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में बिगड़ते मानवाधिकार हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उसने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सोशल मीडिया 'एक्स' पर जारी बयान में UKPNP ने कहा कि वैश्विक संस्थानों, विभिन्न देशों की सरकारों और मानवाधिकार संगठनों को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ (EU), ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रूस, चीन, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया से PoJK में कथित रूप से बढ़ती हिंसा पर ध्यान देने और कार्रवाई करने की अपील की है। UKPNP ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। पार्टी के अनुसार, PoJK के निवासियों को कानून के दायरे में रहते हुए अपने जीवन, संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा के लिए वैध उपाय अपनाने का अधिकार होना चाहिए। अपने बयान में UKPNP ने मानवाधिकारों से जुड़े कई अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों का उल्लेख किया। UKPNP ने दावा किया कि 5 जून 2026 से अब तक PoJK में 100 से अधिक कश्मीरी मारे जा चुके हैं, जबकि कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैकड़ों लोगों को जबरन लापता किया गया है। बयान में 27 और 28 जुलाई की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। UKPNP के अनुसार, रावलाकोट, मीरपुर और PoJK के अन्य इलाकों में हुई कथित हिंसा में लगभग 40 कश्मीरियों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। UKPNP ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक या गैरकानूनी बल का प्रयोग हुआ है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय पक्षों से इन घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संबंधित पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन कराने के लिए कदम उठाने की अपील की है। UKPNP ने अपने बयान में दोहराया कि मानव जीवन की सुरक्षा, कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय करना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ही क्षेत्र में न्याय, स्थिरता और स्थायी शांति स्थापित करने का आधार बन सकता है।

शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में आ सकते हैं

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। अगर यह दौरा होता है तो यह लगभग सात सालों में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा 2019 में महाबलीपुरम में हुई अनौपचारिक समिट के बाद शी जिनपिंग की पहली यात्रा होगी। वह समिट जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में आई भारी गिरावट से कुछ महीने पहले हुई थी। शी जिनपिंग की यह प्रस्तावित यात्रा अगस्त 2025 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए राजनयिक निमंत्रण के बाद हो रही है। अधिकारियों के मुकाबिक शी जिनपिंग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को अपना समर्थन जताया। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तारित समूह के नेताओं के एक साथ आने की उम्मीद है जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ रही है। इसमें ट्रेड टेंशन, वेस्ट एशिया में टकराव और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर से ब्रिक्स के जरिए सहयोग मजबूत करने की कोशिशें शामिल हैं। उम्मीद है कि इस समिट से भारत और चीन को अनसुलझे बॉर्डर मामलों को मैनेज करते हुए डिप्लोमैटिक बातचीत जारी रखने का मौका मिलेगा। अगर पुष्टि हो जाती है तो शी जिनपिंग का दौरा गलवान के बाद बिगड़े रिश्तों के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे अहम डिप्लोमैटिक बातचीत में से एक होगा और आपसी रिश्तों में और सुधार के संकेतों पर करीब से नजर रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी

छत्तीसगढ़ में 4,577 नए शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित

छत्तीसगढ़ में युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए 4,577 नए शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया, जिससे राज्य में ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़कर 14,948 हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में तंबाकू की रोकथाम से लेकर इसे छोड़ने के लिए मार्गदर्शन, उपचार, शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने और कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई तक एक साथ काम किया जा रहा है।इसी समेकित प्रयास का असर है कि वर्ष 2025-26 में 70,440 लोगों ने तंबाकू छोड़ने के लिए 'काउंसलिंग' ली, जबकि 6,563 लोगों को 'काउंसलिंग' के साथ 'फार्माकोथेरेपी' उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए 4,577 नए शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया, जिससे राज्य में ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़कर 14,948 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (टीओएफईआई) अभियान के तहत वर्ष के दौरान 4,577 नए शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया।पूर्व में घोषित 10,371 संस्थानों को मिलाकर राज्य में अब 14,948 शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इनमें सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण अभियान में कानून के प्रभावी पालन पर भी विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध के उल्लंघन पर वर्ष के दौरान 7,783 चालान कर 10,97,670 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने अथवा उनसे खरीदने के मामलों में 1,088 चालान तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध 1,187 चालान किए गए। अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कृषि, शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को भी जोड़ा गया।

जुबैर बलोच पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी

पाकिस्तान के कराची शहर के ल्यारी इलाके में गुरुवार शाम जेल में बंद गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आई है। इस हमले में जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 राहगीर भी गोली लगने से जख्मी हो गए। तीनों को तुरंत कराची के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाकीवाड़ा पुलिस के मुताबिक, करीब 40 साल के जुबैर बलोच को मुख्य चाकीवाड़ा रोड पर गोली मारी गई। दक्षिण कराची के DIG सैयद असद रजा ने बताया कि जुबैर अपने घर के बाहर सिंगू लेन में बैठा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद हमलावर पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जुबैर के सीने और पेट में कई गोलियां लगी हैं और ताजा अपडेट यह है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। घायल हुए 2 राहगीरों में से एक की हालत भी गंभीर बताई गई है। DIG असद रजा ने बताया कि पुलिस इस हमले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। इसमें गैंगवार और निजी दुश्मनी दोनों एंगल शामिल हैं। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि जुबैर बलोच को वर्ष 2012 में 7 आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वह जनवरी 2025 में जेल से रिहा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। घटना के दौरान पास की एक दुकान के मालिक ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले।

बीते तीन दिनों से पूरे नेपाल में विरोध-प्रदर्शन जारी

बीते तीन दिनों से पूरे नेपाल में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। कप्तानगंज में हिंदू युवक की मौत को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनसरी के देवानगंज में झड़प हुई थी। एक व्यक्ति की अब तक मौत हो गई थी। 24 लोग घायल। बिहार से सटे वीरगंज में हिंदू संगठनों ने मशान जुलूस निकाला है। सहायक मुख्य ज़िला अधिकारी क्षेत्रराज बराल ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा के पास सांप्रदायिक हिंसा में तीन लोगों की मौत के बाद नेपाल के सुनसरी ज़िले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, भारत के बिहार राज्य से सटे दक्षिणी नेपाल के सुनसरी ज़िले के कप्तानगंज में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और नेपाल के सुनसरी और सिराहा ज़िलों के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है।नेपाल के PM बालेनद्र शाह ने गुरुवार को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। देश के नाम टीवी पर दिए गए संबोधन में शाह ने कहा कि सरकार हाल ही में हुई हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएगी। नेपाल के सुनसरी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा अब कई शहरों में फैल गई है और पुलिस प्रशासन हालात को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले चार दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़, पत्थरबाज़ी और पुलिस के साथ झड़प की खबरें आई हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सड़कों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए सेना को हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े हैं। इस हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में प्रदर्शनकारी, स्थानीय नागरिक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इस अशांति के कारण कई जगहों पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। यह भी खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी है।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद होती है। यही वह मंच है जहां सरकार अपनी नीतियों का पक्ष रखती है, विपक्ष जवाबदेही तय करने की कोशिश करता है और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। ऐसे में सदन के भीतर रखी जाने वाली हर जानकारी का तथ्यात्मक रूप से सही होना बेहद आवश्यक है। यदि किसी बयान की सत्यता पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संसद की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है।दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अब संसद में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी, जबकि सरकार अपने बयान पर कायम है। यह विवाद एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि संसद में दिए गए हर बयान की जिम्मेदारी संबंधित मंत्री पर होती है। संसदीय परंपराएं भी यही कहती हैं कि यदि किसी तथ्य को लेकर विवाद हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाना चाहिए।हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ऐसे मुद्दे वास्तविक तथ्यों की जांच से पहले ही राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। इससे बहस का केंद्र जनहित के मुद्दों से हटकर केवल राजनीतिक टकराव तक सीमित हो जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से जवाब मांगना है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह हर सवाल का जवाब तथ्यों और पारदर्शिता के साथ दे।जरूरत इस बात की है कि विवादित घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच एजेंसियां और संसदीय प्रक्रियाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करें। यदि किसी मंत्री का बयान सही है तो उसे प्रमाणों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए, और यदि कहीं तथ्यात्मक गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। इसी तरह विपक्ष को भी आरोप लगाने से पहले ठोस साक्ष्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।लोकतंत्र की मजबूती केवल बहस से नहीं, बल्कि सत्य और जवाबदेही से आती है। संसद का सम्मान तभी बना रहेगा जब वहां तथ्यों को राजनीति से ऊपर रखा जाएगा। जनता की अपेक्षा भी यही है कि संसद आरोपों और प्रत्यारोपों का मंच बनने के बजाय समस्याओं के समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सर्वोच्च संस्थान बनी रहे।

जितेंद्र सिंह पर कांग्रेस का प्रिविलेज मोशन
केसी वेणुगोपाल बोले- संसद को गुमराह करने का देना होगा जवाब

कांग्रेस का दावा है कि मंत्री का यह बयान वास्तविक घटनाक्रम से मेल नहीं खाता। केसी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान गोली चली थी और इस घटना में घायल हुए व्यक्ति का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके अनुसार, उपलब्ध तथ्यों और घटनाओं के बावजूद मंत्री ने सदन में ऐसा बयान दिया, जो वास्तविकता के विपरीत था।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (P A C) के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) का नोटिस देकर संसद में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया। वेणुगोपाल ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप करते हुए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए नोटिस में केसी वेणुगोपाल ने नियम 222 के तहत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने जवाब में कहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई थी। मंत्री ने सदन में कहा था कि उस दिन केवल आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और जब गोली चली ही नहीं तो फायरिंग का आदेश देने का सवाल भी नहीं उठता।कांग्रेस का दावा है कि मंत्री का यह बयान वास्तविक घटनाक्रम से मेल नहीं खाता। केसी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान गोली चली थी और इस घटना में घायल हुए व्यक्ति का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके अनुसार, उपलब्ध तथ्यों और घटनाओं के बावजूद मंत्री ने सदन में ऐसा बयान दिया, जो वास्तविकता के विपरीत था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संसद को जानबूझकर गुमराह करने का मामला है।वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि संसदीय परंपराओं के अनुसार किसी भी मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सदन के पटल पर रखी जाने वाली हर जानकारी की पूरी तरह पुष्टि करे। यदि कोई मंत्री जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। इसी आधार पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए ताकि इसकी विस्तृत जांच हो सके और यदि आरोप सही पाए जाएं तो संसदीय नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस प्रिविलेज मोशन के बाद संसद में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव और तेज होने की संभावना है। अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह तय करना होगा कि विशेषाधिकार हनन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार किया जाता है, तो इसे आगे की जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है।

राहुल गांधी से पूछा घायल पुलिसवालों का सवाल जवाब में बोले- 'आप BJP के हो क्या?', वीडियो वायरल

दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन का दृश्य सभी ने देखा। पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले यहां तक की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल भी करना पड़ गया था। इसमें प्रदर्शनकारी से लेकर पुलिस के जवान तक घायल हुए थे। गंभीर चोटें आई थी। इसी को लेकर पुलिस के जवानों के परिवारों ने मीडिया के सामने अपना दर्द साझा किया। इसके कुछ ही देर बाद संसद परिसर में राहुल गांधी से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही राहुल गांधी ने रिपोर्टर से कहा- भैया आप BJP के हो क्या?, अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज शुक्रवार को घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उस दिन उनके परिवारों पर क्या बीती। एक घायल ACP की पत्नी ने कहा कि जब उनके पति घायल हालत में घर लौटे तो पूरा परिवार सदमे में था। उन्होंने कहा कि उनकी दो साल की बेटी भी इस घटना से काफी डर गई थी। वहीं, एक घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनके पिता पर हमला किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता पहले भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो रह चुके हैं। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां वे कई घंटे तक बेहोश रहे। परिवारों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि असली उपद्रवियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ समय बाद संसद भवन परिसर में मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। पत्रकार ने घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। लेकिन सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि राहुल गांधी ने कहा- भैया, आप BJP के हो क्या? बता दें इससे पहले राहुल गांधी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की बात भी कही थी। इस पूरे मामले को लेकर संसद में भी टकराव देखने को मिला। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ 29 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर प्रिविलेज नोटिस पेश किया, जिससे यह और बढ़ गया। इसी के जवाब में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी।

CM शुभेंदु अधिकारी पर हमले की कथित साजिश जैश के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी से हड़कंप

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की प्लानिंग का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। STF ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मेंबर हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को शक है कि जैश के इस संदिग्ध आतंकवादी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का प्लान था। आतंकी के पास से रिकवरी किए गए मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किया गया जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी हामिद मंडल, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट का करीबी है। आतंकी को कल (गुरुवार) को देर रात बर्धमान के रेनेसां टाउन शिप इलाके में स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया आतंकी हामिद मंडल पिछले लगभग 2 से 3 महीने से इलाके में एक किराए के एक फ्लैट में रह रहा था। सामने आई जानकारी के अनुसार, बंगाल STF द्वारा इस पूरे मामले में विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। जांच एजेंसी कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग कर सकती है। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के नेटवर्क, संपर्कों तथा कथित गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। मामले से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों और साजिश के पहलुओं की भी जांच जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। पुलिस ने बीरभूम जिले के नलहाटी इलाके में एक खाली पड़े घर में से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसी पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार, जब्त किए गए विस्फोटकों में 800 KG से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, 1,200 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक, 105 डेटोनेटर और 36 डेटोनेटिंग फ्यूज कॉइल बरामद किए गए हैं।

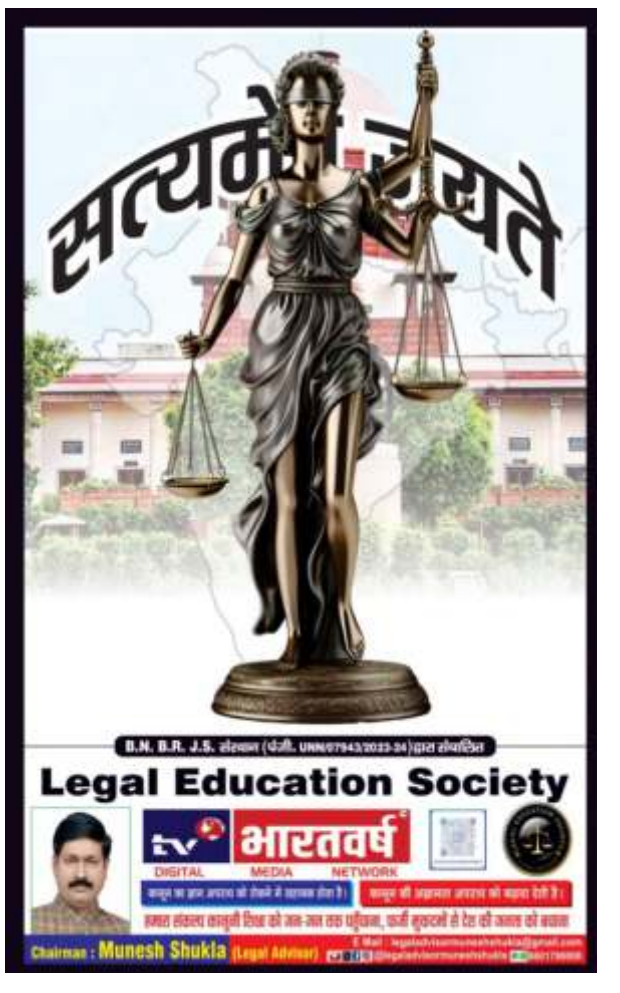

CSAB स्पेशल काउंसलिंग में 15,423 खाली सीटों पर मिलेगा एडमिशन का मौका

अगर JoSAA (जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी) की काउंसलिंग के बाद भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं मिली है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) ने स्पेशल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस काउंसलिंग के जरिए देश के प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बची हुई 15,423 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। यह प्रक्रिया उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो JoSAA के किसी भी राउंड में सीट हासिल नहीं कर पाए या बेहतर विकल्प की तलाश में हैं।JoSAA 2026 की काउंसलिंग पूरी होने के बाद केंद्र सरकार से वित्तपोषित 119 इंजीनियरिंग संस्थानों में हजारों सीटें खाली रह गईं। इन सीटों में 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), 27 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIEST), शिबपुर और 60 सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (GFTIs) शामिल हैं। इन सभी संस्थानों में प्रवेश JEE Main 2026 की ऑल इंडिया रैंक (AIR) के आधार पर दिया जाएगा।CSAB द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल 15,423 खाली सीटों में से 13,156 सीटें जेंडर-न्यूट्रल श्रेणी की हैं, जिन पर सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं, 2,267 सीटें विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में छात्राओं के लिए भी यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।इंजीनियरिंग की सबसे लोकप्रिय शाखाओं में शामिल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। इस ब्रांच में कुल 3,098 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें NITs में 503 सीटें, IIEST शिबपुर में 17 सीटें, IIITs में 1,173 सीटें और GFTIs में 1,405 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख शाखाओं में भी कई सीटें उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों के पास अपनी पसंद के संस्थान और ब्रांच चुनने का अच्छा मौका है।CSAB स्पेशल काउंसलिंग में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जिनके पास JEE Main 2026 की वैध ऑल इंडिया रैंक (AIR) है और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यह काउंसलिंग विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, जिन्हें JoSAA के माध्यम से सीट नहीं मिली या जो उपलब्ध खाली सीटों पर नया विकल्प तलाशना चाहते हैं।CSAB स्पेशल काउंसलिंग 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार 3 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पहला मॉक सीट अलॉटमेंट 31 जुलाई को जारी किया जाएगा, जबकि चॉइस फिलिंग और ऑटो-लॉकिंग की प्रक्रिया 5 अगस्त दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद 6 अगस्त को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 10 अगस्त तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस जमा करने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए जो छात्र अब तक एडमिशन से वंचित हैं, उनके लिए CSAB स्पेशल काउंसलिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने का एक महत्वपूर्ण और अंतिम अवसर साबित हो सकती है।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का परिणाम जारी, जनरल और ओबीसी दोनों की कटऑफ 250 पार गई

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट से अपना परिणाम रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने महिला और पुरुष वर्ग की कैटेगिरी वाइज कटऑफ भी जारी कर दी है। जनरल पुरुष की कटऑफ 258.03661 पर लगी है।यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर समेत विभिन्न पदों पर इस भर्ती की लिखित परीक्षा में 76184 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है। रिटन एग्जाम के बाद ये अब उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण में डीवी पीएसटी की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई है। जिसमें सभी चयनित अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए उपलब्ध हैं।जिन भी उम्मीदवारों ने 08, 09 और 10 जून 2026 को यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा दी है, वो अपना परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे बताए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन का उप-कप्तान बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया

जसप्रीत बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज

भारतीय टीम अगस्त में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने हाल ही में टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया था। इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन का सेलेक्शन फिटनेस के अधीन हुआ था। यानी कि इस सीरीज में खेलने के लिए दोनों प्लेयर्स को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका सीरीज के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है जो भारत के लिए अच्छी खबर है।बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें फिटनेस टेस्ट में पास कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। बुमराह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच से बाहर रहे थे। हालांकि, अब वह पूरी तरह ठीक हैं और दोनों टेस्ट मैचों में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि जसप्रीत बुमराह चोट से उबर चुके हैं। उन्होंने फिटनेस से जुड़े सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे।वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को यहां से बचे हुए 9 टेस्ट मैचों में से भारत को कम से कम 7 मैच जीतने हैं। इसके बाद होने वाले चुनौतीपूर्ण न्यूजीलैंड दौरे को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल करना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है।

अजिंक्य रहाणे :शुभमन गिल ने उन्हें एक आदर्श खिलाड़ी करार दिया

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लंबे समय तक अपने साथी रहे अजिंक्य रहाणे के बारे में कहा कि उनकी 'प्रतिबद्धता और प्रोफेशनलिज्म' उन्हें सबसे अलग बनाती थी जबकि मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें एक आदर्श खिलाड़ी करार दिया। रहाणे ने 12 साल तक चले अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को गुरुवार को अलविदा कह दिया। इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।रोहित ने एक्स पर लिखा, 'हमने कई सालों तक ड्रेसिंग रूम साझा किया है और मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें कितनी मेहनत लगी है। आपकी प्रतिबद्धता और प्रोफेशनलिज्म आपको हमेशा से दूसरों से अलग बनाता आया है। शानदार करियर के लिए बधाई। ढेर सारी शुभकामनाएं।' भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल ने कहा कि रहाणे ने सबसे मुश्किल समय में नेशनल टीम की अगुवाई की। शुभमन गिल ने लिखा, 'क्या शानदार करियर था, क्या शानदार आदर्श स्थापित किए। अज्जू भाई ने भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे कठिन दौर में हमारा नेतृत्व किया और हमें विश्वास दिलाया कि कुछ भी संभव है। मैदान पर और मैदान के बाहर की यादों और सीख के लिए आपका आभार। अगली पारी के लिए शुभकामनाएं।' रहाणे ने 2020-2021 में कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम की अगुवाई करते हुए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इस दौर में भारत के हेड कोच रहे रवि शास्त्री ने कहा कि रहाणे ने भारत और मुंबई क्रिकेट की उत्कृष्ट सेवा की। शास्त्री ने कहा, 'भारत के सबसे समर्पित क्रिकेटरों में से एक, जो मेरे कोच रहते हुए टीम के अभिन्न अंग थे और जिन्होंने मुंबई और भारतीय क्रिकेट के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दीं। शाबाश जिंक्स।'

शर्मिला धनखड़ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के शॉट पुट एफ57 इवेंट में भारत की शर्मिला धनखड़ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया।शर्मिला कॉमनवेल्थ पैरा-एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पैरा-एथलीट बन गईं। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ भारत का 20 साल का इंतजार खत्म किया, बल्कि हमवतन शिल्पा शायला के साथ मिलकर एक लैंडमार्क डबल पोडियम फिनिश भी हासिल किया। शिल्पा ने कांस्य पदक जीता।शर्मिला की इस जीत के पीछे संघर्ष और हिम्मत की एक लंबी कहानी छिपी है। उनका जीवन आसान नहीं रहा। महज 2 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उनका एक पैर प्रभावित हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता छोटे किसान थे और मां दृष्टिबाधित थीं, इसलिए उनका सही इलाज नहीं हो सका। हालात ऐसे बने कि कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई।मात्र 26 साल की उम्र में शर्मिला को उनके पति ने छोड़ दिया। यह उनके लिए बेहद मुश्किल समय था, क्योंकि उनके दो बेटियां भी हैं। हालांकि दो साल बाद उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटीं। 28 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की और अजीत उनके जीवन में आए। अजीत ने उन्हें पैरा-एथलेटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया।2018 में उन्हें हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर की नौकरी मिली थी, लेकिन हड़ताल खत्म होते ही नौकरी भी चली गई। यह उनके लिए बड़ा झटका था। आर्थिक तंगी इतनी गंभीर थी कि 2023 में ट्रेनिंग का खर्च उठाने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और किराए के मकान में रहना पड़ा। आज उनकी दोनों बेटियां भी उनकी राह पर चल रही हैं। 17 साल की बड़ी बेटी अनुज जेवलिन थ्रो में और 13 साल की छोटी बेटी लक्ष्मी लॉन्ग जंप में स्टेट लेवल की खिलाड़ी हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद शर्मिला ने कहा, "मैं यह पदक अपनी मां को समर्पित करूंगी। मेरी मां अंधी हैं, और हर तरफ से बुराई के बावजूद, वह बचपन से ही मेरा साथ दे रही हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी मां का सपना पूरा किया।

मंदिर की संकरी चट्टान में फंसा भक्त

मोक्ष के चक्कर में गई जान

तमिलनाडु के एक मंदिर में संकरी चट्टान में फंसकर 36 साल के श्रद्धालु की मौत हो गई. इसके बाद उसी जगह फंसी एक महिला का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

क्या सच में एक पतली चट्टान के बीच से निकलने पर मोक्ष मिलता है? तमिलनाडु के एक मंदिर में हुई दर्दनाक घटना के बाद यह सवाल फिर से चर्चा में है. एक 36 वर्षीय श्रद्धालु की इसी संकरे रास्ते में फंसने से मौत हो गई. इसके बाद कुछ महीने पुराना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला उसी जगह पर फंसी हुई नजर आ रही है. यह हादसा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित अरुणाचल पहाड़ी पर हुआ. यहां हर साल हजारों श्रद्धालु 14 किलोमीटर लंबी गिरिवलम (परिक्रमा) करते हैं. इसी रास्ते में इडुक्कू पिल्लयार मंदिर के पास एक बेहद संकरा चट्टानी रास्ता है, जिसे स्थानीय लोग 'मोक्ष मार्गम' यानी 'मुक्ति का रास्ता' कहते हैं. 24 जुलाई को आंध्र प्रदेश के रहने वाले 36 वर्षीय मणिकुमार दर्शन के लिए यहां पहुंचे थे. परिक्रमा के दौरान उन्होंने भी मोक्ष मार्गम से निकलने क कोशिश की. लेकिन चट्टानों के बीच बनी बेहद तंग जगह में उनका शरीर फंस गया. कुछ ही मिनटों में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. बाद में फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी.

आस्था से बढ़कर है इंसानी जिंदगी

इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धार्मिक आस्था के साथ-साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. अगर समय रहते उचित इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में भी ऐसे हादसे दोहराए जा सकते हैं. मोक्ष की तलाश में कोई श्रद्धालु अपनी जान गंवा दे, यह किसी भी समाज के लिए चिंता की बात है.

कुत्ते ने सड़क पर सुसु किया तो लगेगा फाइन

अगर आप अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकलते हैं, तो सिर्फ उसका पॉटी उठाना ही काफी नहीं होगा. स्विट्जरलैंड के एक शहर में कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए एक सख्त नियम बनाया है. यहां अगर कुत्ता सड़क या किसी दीवार के पास सुसु कर देता है, तो उसके मालिक को उसे पानी डालकर साफ भी करना होगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.स्विट्जरलैंड के इटालियन भाषी इलाके टिसिनो के छोटे से शहर कियासो ने यह अनोखा नियम बनाया है.

5 महीने से था बेरोजगार

AI की मदद से मिली 1.5 करोड़ की जॉब

आज के समय में नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अच्छी डिग्री और सालों का अनुभव होने के बावजूद कई लोगों को लगातार इंटरव्यू देने पड़ते हैं और अच्छी नौकरी नहीं मिलती. ऐसे ही एक शख्स की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

इस शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने करीब पांच महीने तक नई नौकरी खोजी, लेकिन बार-बार निराशा ही हाथ लगी. आखिर में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और उसकी यही रणनीति काम कर गई. अब उसे करीब ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नई नौकरी

मिल गई है. इस शख्स ने अपनी कहानी रेडिट पर शेयर की. उसने बताया कि वह लगभग 10 साल तक एक ही कंपनी में काम करता रहा था. इस दौरान उसे तीन बार प्रमोशन भी मिला. लेकिन फरवरी के आखिर में अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. यह फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

जन्म लेते ही बच्चों पर हो जाता है मालिक का हक

गुलामों के द्वीप की अनूठी कहानी

दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है. गुलामी को खत्म हुए भी कई देशों में 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा द्वीप है, जहां आज भी कुछ लोग जन्म लेते ही किसी और की संपत्ति माने जाते हैं. उन्हें बचपन से ही मालिक की सेवा करनी पड़ती है. बिना मजदूरी के खेतों में काम करना, घर के सारे काम संभालना और मालिक के हर आदेश का पालन करना उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है. इतना ही नहीं, कई लोगों का आरोप है कि यहां गुलाम महिलाओं के साथ यौन शोषण और मारपीट जैसी घटनाएं भी होती हैं.यह कहानी इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप की है, जो बाली के मशहूर समुद्री तटों से महज दो घंटे की दूरी पर है. बाहर से देखने पर

यह जगह खूबसूरत झरनों, पहाड़ियों और समुद्र के बीच बसा एक शांत पर्यटन स्थल नजर आता है, लेकिन इसके भीतर सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा आज भी सांस ले रही है, जिसे दुनिया गुलामी कहती है.

'मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आजाद हों'

सुम्बा के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, जो खुद इसी व्यवस्था में पैदा हुआ, अपनी पहचान छिपाते हुए बताता है कि बचपन से ही उसे मालिक के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. वह कहता है, अगर मैं ठीक से काम नहीं करता था तो मुझे पीटा जाता था. मुझ पर पानी फेंका जाता था. स्कूल से लौटते ही खेतों में काम करना पड़ता था.

'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च पर सनी देओल ने 29 साल बाद राजकुमार संतोषी के साथ काम करने का अनुभव साझा किया. जानिए उन्होंने अपनी सुपरहिट जोड़ी, फिल्म और इमोशनल कहानी को लेकर क्या कहा.

29 साल बाद राजकुमार संतोषी संग सनी देओल

बॉलीवुड के 'ढाई किलो के हाथ' वाले स्टार सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर इमोशनल कहानी लेकर लौट रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर लॉन्च मंगलवार को हुआ, जहां सनी ने फिल्म, अपनी मां और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ दोबारा काम करने को लेकर दिल की बात कही. 68 साल के सनी देओल ने कहा कि उन्होंने 'बंटवारा 1947' अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित की है. उन्होंने बताया कि फिल्म में शबाना आजमी के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल मां-बेटे जैसा महसूस हुआ. ट्रेलर में सनी का एक डायलॉग सबसे ज्यादा चर्चा में है- मां को हिंदू-मुस्लिम में मत बांटिए... मां अपने आप में एक मजहब है. यही लाइन फिल्म के सबसे दमदार और इमोशनल मोमेंट्स में से एक मानी जा रही है. सनी देओल ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ अपनी शानदार बॉन्डिंग का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों की सोच हमेशा से एक जैसी रही है.

यूपी में जनगणना की तैयारी तेज,

चुनाव से पहले जातीय गणना बनेगी बड़ी चुनौती

उत्तर प्रदेश में डेढ़ दशक बाद होने वाली जनगणना की तैयारियां तेज हैं। इस बार जातीय गणना भी शामिल होगी। विधानसभा चुनाव और जनगणना के बीच तालमेल बड़ी चुनौती है। प्रशासन नवंबर-दिसंबर में प्रक्रिया पूरी करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ दशक बाद होने जा रही जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मामला सिर्फ आबादी की गिनती तक सीमित नहीं है, क्योंकि जनगणना का दूसरा चरण ऐसे समय प्रस्तावित है, जब अगले साल उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी इस बात पर चर्चा तेज है कि जनगणना और चुनावी कार्यक्रम के बीच तालमेल कैसे बनाया जाएगा। देश में जनगणना दो चरणों में कराई जानी है। पहला चरण, जिसमें मकानों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा सर्वे शामिल था, जून तक पूरा किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। इस बार पहली बार जातीय गणना को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मार्च से मई के बीच समाप्त हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 के दौरान कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है और तय समय पर ही होंगे। वहीं जनगणना भी कानूनी प्रक्रिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों बड़े काम एक साथ कैसे पूरे होंगे। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जनगणना के लिए करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जिनमें बड़ी संख्या शिक्षकों की होती है। चुनावी ड्यूटी, बोर्ड परीक्षाएं और पंचायत चुनाव जैसी जिम्मेदारियों के बीच जनगणना के लिए समय निकालना आसान नहीं होगा। प्रशासनिक स्तर पर इस बात पर मंथन चल रहा है कि यदि चुनाव से पहले पर्याप्त समय मिल जाए तो जनगणना का दूसरा चरण नवंबर या दिसंबर में पूरा कराया जा सकता है। ऐसा होने पर प्रशिक्षण, डेटा संग्रह और अन्य औपचारिकताएं भी समय रहते पूरी हो सकेंगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जातीय गणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों और राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आगामी विधानसभा चुनाव मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही होंगे। नई जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में परिसीमन (Delimitation), संसाधनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पुरानी फोटो बनी गिरफ्तारी की वजह, अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

दुबग्गा कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, करीब चार-पांच साल पुरानी एक फोटो इस गिरफ्तारी की वजह बनी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर बरावन कला क्षेत्र में कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने बरावन कला निवासी शिवम साहू (29) पुत्र सिद्धनाथ साहू को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपी शिवम साहू ने बताया कि उसने लगभग चार-पांच साल पहले इसी तमंचे और कारतूस के साथ अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी। वह इस फोटो को दिखाकर लोगों पर रौब जमाता था। हाल ही में उसने यह फोटो अपने एक दोस्त को भेजी, जिसने इसे गांव के अन्य लोगों को दिखा दिया। फोटो की चर्चा फैलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शिवम ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि यदि उसने वह फोटो किसी को नहीं भेजी होती, तो शायद वह पकड़ा नहीं जाता। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 230/2026 के तहत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

यूपी से हज 2027 के लिए 22,510 यात्रियों का चयन, महिलाओं की संख्या में 32% बढ़ोतरी

लखनऊ समेत पूरे प्रदेश से हज पर जाने वाले यात्रियों का चयन हो गया है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश से 22,510 यात्री रवाना होंगे। इन लोगों का हज यात्रा के लिए चयन मुंबई स्थित हज कमेटी आफ इंडिया की कुर्रा (लॉटरी) प्रक्रिया में हुआ है। चयन की सूचना सभी आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। हज यात्रा के लिए चयनित लोगों में 11,947 पुरुष हैं और 10,563 महिलाएं हैं। जारी वर्ष में महिला हज यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी है । वर्ष 2026 में 7990 महिलाओं ने आवेदन किया था, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 10563 पहुंच गई। 2573 महिलाओं ने अधिक आवेदन किया। वहीं वर्ष 2025 में महिला आवेदकों की संख्या 6407, वर्ष 2024 में 8486, वर्ष 2023 में 11690 और वर्ष 2022 में 3442 दर्ज की गई। विगत वर्ष की तुलना महिला हज यात्रियों की संख्या 32% तक बढ़ी है। नामहरम श्रेणी की 55 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को उनके धार्मिक जज़्बे से जोड़कर देखा जा रहा है। चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक पहली किश्त के रूप में ₹ 1,52,300 हज कमेटी आफ इंडिया के यूनियन बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा करना होगा। भुगतान हज सुविधा एप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। राशि जमा करने के बाद आवेदकों को पे-इन स्लिप, हस्ताक्षरित हज आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट संबंधी घोषणा पत्र और मेडिकल स्क्रीनिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट अपनी लाग-इन आइडी से अपलोड करना होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय में ई-ऑफिस की शुरुआत, 1.25 लाख से अधिक छात्रों को मिली डिजिटल डिग्री

लखनऊ विश्वविद्यालय में आज 31 जुलाई से पेपरलेस वर्किंग शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने ई-ऑफिस का उद्घाटन किया। दीक्षांत समारोह KGMU के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में मनाया गया। कुलाधिपति ने कुल 1 लाख 25 हजार 239 स्टूडेंट्स को डिजिटल डिग्री प्रदान की। कुलपति जेपी सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय में 44 देशों के युवा पढ़ रहे हैं। इस समय कुल छात्र-छात्राओं में 93536 स्नातक, 31006 परास्नातक, 419 डिप्लोमा और 30 ऑनलाइन शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा 248 रिसर्चर को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। समारोह में कुल 204 पदक 111 मेधावियों को दिए गए, जिनमें 80 छात्राओं और 31 छात्रों के नाम शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने की। नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर मुख्य अतिथि रहे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी बुलाए गए थे लेकिन वह नहीं आ सके। अतिथियों में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी समारोह में शामिल हुईं।

लखनऊ में स्कॉर्पियो से आकर युवक पर हमला

पीजीआई इलाके के एल्डिको स्थित बलिया हाउस में एक युवक पर स्कॉर्पियो से आकर लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों के पास लोहे के रॉड और कील वाले डंडे थे। युवक को इतना पीटा कि उसके हाथ-पैर तोड़ डाले। उसके सिर में भी गंभीर चोट आई है। पीड़ित फतेहपुर जिले के लालौली थाना क्षेत्र के ग्राम कोर्रा कनक निवासी बिपिन सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। बिपिन वर्तमान में बलिया हाउस में रहकर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे वह अपने घर के बाहर रिश्तेदारों और परिचितों के साथ बैठे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो से पहुंचे आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार, हमलावरों ने लोहे के रॉड और कील लगे डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। घायल अवस्था में छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए वे फरार हो गए। बिपिन के साथियों ने उन्हें तत्काल पीजीआई ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। पीजीआई पुलिस ने बिपिन सिंह की तहरीर के आधार पर छह नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रद्द, 136 यात्रियों को हुई परेशानी

लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान शुक्रवार को अचानक रद्द कर दी गई। उड़ान रद्द होने से 136 यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। बाद में एयरलाइन अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (आईएक्स 2173) लखनऊ से दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए निर्धारित थी। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, विमान निर्धारित समय पर रवाना नहीं हुआ और यात्रियों को लगातार देरी की सूचना दी जाती रही। शाम करीब 4:30 बजे डिस्प्ले पर अचानक उड़ान रद्द होने की घोषणा की गई। उड़ान रद्द होने की जानकारी मिलते ही यात्री भड़क गए और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद एयरलाइंस अधिकारियों ने यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने या दूसरी उड़ान से दिल्ली भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यात्री शांत हुए। बाद में, दिल्ली जाने वाले इन यात्रियों को दूसरे विमान से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि, उड़ान रद्द होने के कारण यात्री समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सके, जिससे उनमें काफी नाराजगी रही। इसी बीच, सूत्रों ने यह भी बताया कि लखनऊ से तड़के 3:15 बजे दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (आईएक्स 193) को भी ऑपरेशनल कारणों से 1 अगस्त शनिवार को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों विमानों को ऑपरेशनल कारणों से ही रद्द किया गया।

उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाओं पर डीएम का सख्त एक्शन, सीएचओ और आशा कर्मी को बर्खास्त करने के निर्देश

उन्नाव के स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में बिछिया ब्लॉक की एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और एक आशा कर्मी को लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए। वहीं, नवाबगंज और हसनगंज के चिकित्सा अधिकारियों की खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि बिछिया ब्लॉक के धूरकेत उपकेंद्र पर तैनात सीएचओ शिवांगी सिंह और डीह उपकेंद्र की आशा कर्मी शैल सिंह कई महीनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही थीं। विभागीय स्तर पर कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने दोनों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए। बैठक में नवाबगंज और हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिली। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों को फटकार लगाते हुए सभी स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि आशा और आशा संगिनी की मिलीभगत से निजी अस्पतालों में प्रसव कराने की शिकायतों पर नियमित निगरानी रखी जाए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने और इस संबंध में जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने आशा और आशा संगिनी का मानदेय प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने, एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम में सुधार लाने और जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत उन्होंने घर-घर सर्वे कर खांसी, जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसे रोगों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही, नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनका टीकाकरण पूरा कराने पर भी जोर दिया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात दोहराई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जे.आर. सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

उन्नाव में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का हिस्सा धंसा, उद्घाटन के 16 दिन बाद ही सामने आई खामी

उन्नाव में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का एक हिस्सा धंस गया। इस एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 16 दिन पहले ही हुआ था। गुरुवार दोपहर किलोमीटर संख्या 30.6 के पास सड़क धंसने का वीडियो सामने आया। इसमें सड़क का हिस्सा टूटा दिखाई दे रहा है। निर्माण एजेंसी पीएनसी (PNC) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत जारी है। पैबंद लगाए जा रहा है। सड़क किस वजह से धंसी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। NHAI की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह एक्सप्रेस-वे 4,700 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास 5 जनवरी 2022 को हुआ था। करीब 1650 दिन बाद, 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। 63 किलोमीटर लंबा यह देश का पहला बैरियर-लेस एक्सप्रेस-वे है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में कहा था कि हमारे हाईवे अमेरिका से भी अच्छे बनेंगे। मेरे विभाग में पैसे की कमी नहीं है। आप मांगते हुए थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा।

उन्नाव ट्रैफिक पुलिस को मिली अत्याधुनिक इंटरसेप्टर कार, एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी

उन्नाव में सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अत्याधुनिक इंटरसेप्टर कार मिल गई है। शुक्रवार दोपहर तीन बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जय प्रकाश सिंह ने नई इंटरसेप्टर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन अब प्रमुख हाईवे, कॉरिडोर और व्यस्त मार्गों पर गश्त कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखेगा। एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि इंटरसेप्टर कार अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। नई व्यवस्था से नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। इंटरसेप्टर कार ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, गलत दिशा में वाहन चलाना तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी करेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि सड़क हादसों का प्रमुख कारण यातायात नियमों की अनदेखी है। इंटरसेप्टर कार के संचालन से वाहन चालकों में अनुशासन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रखी जा सकती है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा सहित यातायात पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इंटरसेप्टर कार के संचालन से जिले की यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। सड़क सुरक्षा अभियान को नई मजबूती मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आगे भी सड़क सुरक्षा अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्करी गिरोह, 75 लाख का गांजा बरामद

उन्नाव पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए करीब 75 लाख रुपये मूल्य का 1 क्विंटल 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। थाना बारासगवर पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गांजे से भरा ट्रक, एक स्विफ्ट डिजायर कार, छह मोबाइल फोन और 5,550 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि गुरुवार को धानीखेड़ा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाटन की ओर से आ रहे एक ट्रक और उसके साथ चल रही स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर महेशखेड़ा चौराहे पर बैरियर लगाकर दोनों वाहनों को रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक में गारनेट पाउडर की बोरियों के बीच छिपाई गई चार बोरियों और स्विफ्ट डिजायर कार से एक बोरी में कुल 1.51 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। मौके से रायबरेली निवासी राहुल सिंह, उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर निवासी विशाल दास तथा उन्नाव निवासी अभिषेक यादव, राम सिंह, अरविंद यादव और विशाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रक को ओडिशा भेजा गया था। वहां बिल्डिंग मैटेरियल के साथ गुप्त रूप से गांजा भी लोड कराया गया। गांजा ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से खरीदा गया था और उसे उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड पहुंचाया जाता था। आरोपियों ने बताया कि गांजा करीब 6 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर ऊधमसिंह नगर में 8,500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता था। पुलिस के अनुसार, उत्तराखंड में अशोक उर्फ जग्गा नाम का व्यक्ति इसकी सप्लाई करता था। तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए गांजे को गारनेट पाउडर की बोरियों के बीच छिपाया था। बाहर से ट्रक पूरी तरह बिल्डिंग मैटेरियल से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सघन तलाशी के दौरान चार बोरियां ट्रक से और एक बोरी कार से बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए कई आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में नामजद रह चुके हैं। पुलिस का मानना है कि यह लंबे समय से सक्रिय अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह है।

उन्नाव में गंगा का जलस्तर घटा, प्रशासन ने फिर भी रखा अलर्ट

उन्नाव में कई दिनों से लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर करीब 15 सेंटीमीटर कम हुआ है। इसके बावजूद नदी का पानी शुक्लागंज समेत प्रमुख घाटों तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन सतर्कता बरकरार रखते हुए बाढ़ चौकियों और संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 110.650 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह इसी समय यह 110.850 मीटर था। यानी एक दिन में जलस्तर में करीब 15 सेंटीमीटर की कमी आई है। इससे पहले रविवार शाम छह बजे जलस्तर 110.910 मीटर था। सोमवार और मंगलवार को इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और बुधवार दोपहर एक बजे यह 111.050 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 112 मीटर से करीब 35 सेंटीमीटर नीचे है। यहां खतरे का निशान 113 मीटर निर्धारित है। हालांकि जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे है, लेकिन नदी का पानी प्रमुख घाटों तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए प्रशासन किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता और लगातार निगरानी कर रहा है।

शुक्लागंज में नए गंगापुल निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, टोटल स्टेशन सर्वे शुरू

उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में प्रस्तावित नए गंगापुल के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। शुक्रवार को सेतु निगम ने निर्माण स्थल पर समतलीकरण प्रक्रिया के तहत 'टोटल स्टेशन सर्वे' मशीन से नाप-जोख का कार्य शुरू किया। तकनीकी टीम ने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर निर्माण की अगली प्रक्रिया के लिए आवश्यक माप लिए। मौके पर कार्यरत मजदूरों ने बताया कि सेतु निगम ने अगले 15 दिनों के भीतर निर्माण स्थल से शेष मलबा पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शुक्लागंज की ओर से पुल निर्माण का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने नए गंगापुल के निर्माण के लिए पहले ही अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की थी। पुल के नीचे और निर्माण क्षेत्र में बाधा बन रहे कुल 38 मकानों को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया था, जिससे निर्माण कार्य के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकी। शुक्रवार को हुए सर्वेक्षण के दौरान इंजीनियरों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर समतलीकरण और आगे की तकनीकी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के अनुसार, सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर भूमि को समतल करने, निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मशीनों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भगवा वस्त्र पहनकर संसद में प्रदर्शन पर घमासान पप्पू यादव के खिलाफ संत समाज का विरोध तेज

राम मंदिर दान विवाद को लेकर संसद में भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की संत-महंतों ने कड़ी आलोचना की है।अयोध्या, मथुरा और अन्य स्थानों के धार्मिक नेताओं ने इसे भगवा और सनातन परंपराओं का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की।वहीं, इस मुद्दे ने संसद से लेकर धार्मिक संगठनों तक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है।

संसद में राम मंदिर के दान की चोरी के मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन लिया। इस घटना से देशभर के संत-महंत नाराज हो गए हैं। अयोध्या, मथुरा और दूसरे जगहों से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा कि संसद में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यिपूर्ण है। लोकतंत्र में चुने हुए सांसद इस तरह व्यवहार करें, क्या यह सही है? सनातन का अपमान इस तरह किया जाए क्या यह बर्दाश्त किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि उस वक्त राहुल गांधी हंस रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता, तथाकथित अयोध्या सांसद और कुछ अन्य लोग भगवा वस्त्र पहने संतों के गले पकड़कर खींच रहे थे। महंत राजू दास ने सवाल किया कि क्या किसी ने मौलाना या मौलवी का वेश धारण करके इस्लाम के साथ ऐसा व्यवहार किया है? गाजियाबाद से आध्यात्मिक गुरू स्वामी दीपांकर ने भी पप्पू यादव के इस कदम की निंदा की। उन्होंने कहा कि लाखों साधु-संन्यासियों का भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करना पूरी तरह गलत है। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि हरा कपड़ा पहनकर ऐसा कुछ करें? भगवान राम माफ करें या न करें, लेकिन देश इसे माफ नहीं करेगा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है। इसी वजह से सदन में उन्हें कलनेमि कहा जा रहा था। मथुरा में भी संतों ने विरोध जताया। गोवर्धन के जुल्हेदी आश्रम पर साधु-संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कंस के रूप में उनके पोस्टर लगाए और पुतला फूंका। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने भी सख्त कार्रवाई की मांग रखी। साधु-संतों का कहना है कि भगवा वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान का प्रतीक है। संसद जैसे पवित्र स्थान पर इसे इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और उसकी गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि जनआस्था और सनातन परंपराओं का कथित रूप से अपमान करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसे कृत्यों पर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।

मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपि गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा की थाना सूरजपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 12 चोरी के मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अन्य चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को थाना सूरजपुर पुलिस की टीम रेलवे लाइन के पास नियमित वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई देने पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ के लोहियानगर निवासी अरमान उर्फ गब्बर, पुत्र मोहम्मद अय्यूब, और दनकौर के विलासपुर निवासी साहिल उर्फ बेबे, पुत्र युनुस, के रूप में हुई है। वर्तमान में साहिल सूरजपुर की राशिद कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 12 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की वारदातों में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपी लंबे समय से मोबाइल चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने किन-किन क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और इस नेटवर्क में उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं

दोघट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली

उत्तर प्रदेश के बागपत में गोतस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दोघट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित पशु कटान के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार 28 जुलाई 2026 को थाना दोघट क्षेत्र के ग्राम फौलादनगर में प्रतिबंधित पशु कटान का मामला सामने आया था। मौके से प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने पर थाना दोघट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में एक महिला आरोपी और वांछित अभियुक्त जावेद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।इसी क्रम में, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त वाजिद पुत्र भूरा निवासी ग्राम फौलादनगर मिलाना गांव के जंगल में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख वाजिद भूरा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस के साथ ही टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल (UP17V 8469) बरामद की गई है।

मायावती ने समाजवादी पार्टी (SP) पर संकीर्ण जातिवादी सोच रखने का आरोप लगाया

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (SP) पर संकीर्ण जातिवादी सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि SP ने उत्तर प्रदेश में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान दलित और OBC महापुरुषों के नाम पर रखे गए कई जिलों के नाम बदल दिए थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने 'संत रविदास नगर' (भदोही) का नाम बहाल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का आभार जताया और कांशीराम नगर (कासगंज) सहित अन्य पुराने नामों को भी बहाल करने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि SP सरकार ने दुर्भावना और संकीर्ण राजनीतिक मकसद से काम करते हुए BSP शासन के दौरान लिए गए नामकरण के फैसलों को बदला था। मायावती ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से सभी जानते हैं कि मौजूदा UP सरकार ने 'संत रविदास नगर' जिले का दर्जा बहाल कर दिया है। इस जिले को मूल रूप से BSP सरकार ने भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर बनाया था। बाद में समाजवादी पार्टी (SP) सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी सोच के कारण इसका नाम बदल दिया था, और अब इसे फिर से 'संत रविदास नगर' जिले के रूप में बहाल कर दिया गया है। पार्टी इस बहाली के लिए राज्य सरकार की आभारी है। BSP प्रमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चार कार्यकाल के दौरान, उन्होंने प्रशासन को बेहतर बनाने और दलित व OBC समुदायों में जन्मे महान संतों और गुरुओं का सम्मान करने के लिए संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीम नगर जैसे ज़िले बनाए थे। उन्होंने कहा कि SP सरकार का इन नामों को बदलने का फ़ैसला ऐसा है जिसे "लोग कभी नहीं भूलेंगे"।